



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2000/ज्येष्ठ 18, 1922

No. 326]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2000/JYAISTHA 18, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2000

सा.का.नि. 530(अ).— लोक ऋण नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18), की धारा 2 के खंड (2) के उप-खंड (क) के मद (iv) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिवस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्रारूप नियमों के बारे में प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

कोई व्यक्ति, जो प्रारूप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, वह उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक ऋण(संशोधन) नियम, 2000 है ।
(2) ये इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 23 में “जिला मजिस्ट्रेट” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित राजस्व अधिकारी” ।

[फा. सं. 4(3)-पीडी/98]

धीरेन्द्र स्वरूप, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2000

G.S.R. 530(E).— The following draft of certain rules further to amend the Public Debt Rules, 1946 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with item (iv) of sub-clause (a) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received with respect to the draft rules before the expiry of the said period will be considered by the Central Government;

A person desiring to make any objection or suggestion in respect of the draft rules, may forward the same for consideration by the Central Government within the period specified above to the Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi- 110001.

[F. No. 4 (3)-PD/98]

D. SWARUP, Jt. Secy. (Budget)

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Public Debt Rules, 1946, in rule 23, for the words, "the District Magistrate", the following shall be substituted, namely:-

"an Executive Magistrate or a Gazetted Revenue Officer of a State Government".

